

introduce new disciplines in emerging technologies in the existing technical colleges. It is not possible to give estimate of expenditure involved for opening new technical and science colleges merely on the basis of the demand.

(b) As it is contemplated to train technical and science students in the fields where employment opportunities are more, it is proposed to increase the intake of some of the existing courses and introduce new related disciplines.

Students desirous for getting admission in engineering and other technical institutions in the country

3166. SHRI VITHALRAO

MADHAV. AG JADHAV; SHRI PRABHAKAR B. KORE; SHRI H. HANUMANTHAPFA;

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of students who get through every year in XHth standard and what is the number, which is desirous for getting the admission in Medical, Engineering and technical institutions in the country;

(b) what would be the technical manpower created during the Eighth Five Year Plan period; and

(c) in what manner it would be engaged or employed and what is the plan thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMAN-BHAI MEHTA): (a) The information is being collected.

(b) On the basis of the intake of students to technical institutions, who constitute fresh technical manpower for the Eighth Plan, it is estimated that 2.00 lakh Graduate and 3.00 lakh technicians will be added during the Eighth Plan period.

(c) Eighth Plan Emphasizes more opportunities of employment. However, it is not possible specifically to

give figures of employment opportunities available for these technical personnel.

भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं की संवर्ग-समीक्षा

3167. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री 7 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में अंतरांकित प्रश्न 36 के लिए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी IV से श्रेणी III में पदों के उन्नत किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा स्थगनादेश पारित करने की निश्चित तिथि क्या है और उन तिथियों से पूर्व संवर्ग समीक्षा न कराए जाने के क्या कारण एवं गठनाइयाँ थीं ;

(ख) क्या उक्त सेवा की संवर्ग समीक्षा के लिए योजना मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार है ; यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष कब लाया गया था और जुलाई, 1990 तक इस मामले में कितनी बार सुनवाई हो चुकी थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोबर्धन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य न्यायापीठ ने 21-8-87 को अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा में श्रेणी IV के पदों की श्रेणी III में परिवर्तित करने के संबंध में स्थगनादेश जारी किया था । संबंध नियंत्रण प्राधिकरण (16-10-84 तक कामिक विभाग तथा उसके बाद सांख्यिकीय विभाग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के मामले में संवर्ग की समीक्षा करने के लिए मुख्य